भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 807
जिसका उत्तर मंगलवार 07 फरवरी, 2017 को दिया जाना है

कागज मिलों की दशा

807. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम में स्थित मरिगांव तथा कछार जिले की कागज मिलों की दशा के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार उक्त मिलों के वर्तमान प्रबंधन को बदलने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, हां। कछाड़ पेपर मिल (सीपीएम) में उत्पादन बंद हो गया है। तथापि, नगांव पेपर मिल चालू है और उत्पादन कर रही है।

(ख): एचपीसी की दोनों इकाइयों अर्थात् सीपीएम और एनपीएम में उत्पादन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मेघालय राज्य में कोयले के खनन और परिवहन पर लगाए गए संपूर्ण प्रतिबंध की वजह से कोयले की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित हो रहा है।

भारत सरकार ने सीपीएम द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को महसूस करने के पश्चात् कई उपाय किए हैं जिनमें कार्यशील पूंजीगत सहायता और सीपीएम की संचालन संबंधी हानि को कम करने के लिए विशेष रूप से परिवहन की वजह से इसकी प्रचालनात्मक लागतों को पूरा करने हेतु अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पंचग्राम स्टेशन से कछाड़ पेपर मिल के परिसर में भीतर तक मीटर गेज (एमजी) को ब्रॉड गेज (बीजी) में बदलने के लिए सहायता उपलब्ध कराई है।

मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने का कार्य मार्च, 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा जिससे अन्य स्रोतों से कोयला जुटाया जा सकेगा।

(ग): जी, नहीं।

****